

LABOUR DEPARTMENT

The 3rd September, 1987

No. 14 (198)82-2Lab.—In exercise of the powers conferred by section 5 of the Payment of Gratuity Act, 1972 and in supersession of Haryana Government Labour and Employment Department notification No. 12 (66)-78-3Lab, dated the 27th June, 1978, the Governor of Haryana hereby exempts all the units of the Haryana State Electricity Board from the operation of the provisions of the said Act, subject to the following conditions:—

- (a) that the work-charged employees of all units of the H. S. E. B. will not be exempted from the operation of the provision of the Payment of Gratuity Act, 1972.
- (b) that the exemption will be applicable only to the regular/temporary employees working in all such units of the H. S. E. B who are governed under the Civil Service Rules and have not opted for Contributory Provident Fund, and
- (c) that the employees are in receipt of gratuity or pensionary benefits under the Civil Service Rules, which are not less favourable than the benefits conferred under the Payment of Gratuity Act, 1972.

T. D. JOGPAL.

Commissioner & Secretary to Government, Haryana,
Labour and Employment Department.

अम विभाग

दिनांक 3 सितम्बर, 1987

सं० 14(198)82-2 अम.—उपदान संदाय अधिनियम, 1972 की धारा 5 के अन्तर्गत प्रदान की गई शक्तियों का प्रयोग करते हुए और हरियाणा सरकार अम तथा रोजगार विभाग अधिसूचना संख्या 12(66)78-3अम, दिनांक 27 जून, 1978 का अधिक्रमण करते हुए हरियाणा के राज्यपाल इसके द्वारा हरियाणा राज्य बिजली बोर्ड की सभी इकाइयों को उक्त अधिनियम के उपबन्धों के प्रवर्तन से निम्न शर्तों के अधीन रहते हुए छूट प्रदान करते हैं:—

- (क) हरियाणा राज्य बिजली बोर्ड की सभी इकाइयों के निर्धारित कर्मचारियों को उपदान संदाय अधिनियम, 1972 के उपबन्धों से छूट नहीं दी जाएगी,
- (ख) हरियाणा राज्य बिजली बोर्ड की ऐसी सभी इकाइयों में कार्य करने वाले केवल उन्हीं स्थायी/अस्थायी श्रमिकों पर यह छूट लागू होगी जो सरकारी सेवा नियमों के अधीन ह और जिन्होंने अभिदायी भविष्य निधि के लिये विकल्प नहीं दिया है, और
- (ग) कर्मचारी सिविल सेवा नियम के अधीन उपदान या पेंशन के लाभ प्राप्त करते हैं, जोकि उपदान संदाय अधिनियम, 1972 के अधीन प्राप्त लाभों से कम अनुकूल न हों।

टी० डी० जोगपाल,

आयुक्त एवं सचिव, हरियाणा सरकार
अम तथा रोजगार विभाग।